





# 'राजस्थान पुलिस की एस.आई.टी. ने बीते एक साल में पेपरलीक के 244 आरोपी दबोचे'

## डी.जी.पी. उत्कल रंजन साहू ने पेपर लीक माफिया पर गत एक साल में की गई कार्रवाई पर एस.आई.टी. की सराहना की

जयपुर (कांस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) ने पिछले एक साल में "पेपरलीक माफिया" पर शिकंजा कसा है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने पिछले एक साल में पेपर लीक के अनेकानेक अपराधियों और इसमें शामिल गैंग के सरगनाओं की गिरफ्तारी की है। पेपरलीक गिरोह के सरगना, सहयोगी और गलत तरीकों से लाभान्वित परीक्षार्थी आज सलाखों के पीछे हैं। डमी कैडिडेट्स के सहारे चयन के आरोपी भी पकड़े गए हैं। यहां तक कि ईओ-आरओ परीक्षा में पेपर लीक व अनुचित साधनों के उपयोग का पर्दाफाश भी इस टीम ने किया है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में नई सरकार का नेतृत्व संभालने के तुरंत बाद 16 दिसम्बर 2023 को पेपर लीक से सम्बंधित प्रकरणों की गहन जांच और नकल गिरोह से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ करते हुए हताश युवाओं के विश्वास को लौटाने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था। एसआईटी ने प्रदेश में पेपर लीक की रोकथाम के लिए इस सम्बन्ध में दर्ज मामलों में न केवल जांच को त्वरित तरीके से आगे बढ़ाया है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप एस.आई.टी. की इस ताबडतोड़ कार्रवाई का नतीजा है कि, प्रदेश में बीते एक साल में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) की 145 तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड (आरएसएसबी) की 25 परीक्षाएं बिना पेपरलीक संपन्न हो पायीं हैं।

डी.जी.पी. ने बताया कि राजस्थान में जेईएन, उप निरीक्षक पुलिस तथा प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक में सम्मिलित मुख्य गैंग सरगनाओं, उनके सहयोगी तथा गलत तरीके से लाभान्वित हुए परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकांश आरोपी वर्तमान में भी सलाखों के पीछे हैं।

■ राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक करने वाले सरगना, सहयोगी और गलत तरीकों से लाभान्वित परीक्षार्थी समेत 176 लोग आज सलाखों के पीछे हैं। इनमें डमी कैडिडेट्स के सहारे चयनित हुए लोग भी शामिल हैं।

■ डी.जी.पी. उत्कल रंजन साहू का कहना है "एस.आई.टी. की कार्रवाई का नतीजा है कि पिछले 1 साल में आर.पी.एस.सी. की 145 तथा आर.एस.एस.बी. की 25 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हो सकीं।"

एसआईटी द्वारा परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं के बारे में अलग-अलग खतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 2300 से अधिक परिवारों की जांच की जा रही है। अब तक 94 एसआईटी दर्ज की गई है, वहीं पेपर लीक मामलों में 244 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें से 176 आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) पुलिस, एटीएस और एसओजी तथा एसआईटी के प्रमुख वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान एसओजी के थाने पर पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों के सहारे चयन तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट थोक में जारी करने और इनका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से जुड़ी 91 एसआईटी रजिस्टर की गईं।

एसआईटी की जांच में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर अनुचित साधनों के प्रयोग से चयनित होने वालों की संख्या बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ। यह भी एक पेपर लीक जैसी गम्भीर समस्या थी, जो कि अब तक दबी हुई थी। एसआईटी ने इसे उजागर कर परीक्षा प्रणाली में सुधार करवाए है।

एडीजी वी.के.सिंह ने बताया कि एसआईटी ने आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशाषी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी (ईओ/आरओ) भर्ती परीक्षा-2023 की जांच कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनमें पेपर लीक एवं अनुचित साधनों के

उपयोग का पर्दाफाश भी किया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा को निरस्त कर पुनः आयोजन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बेकरिया पेपरलीक प्रकरण में दिसम्बर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 के सिलसिले में थाना बेकरिया जिला उदयपुर में गिरफ्तारशुदा 6 मुल्जिमों की जमानत याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा सुनवाई के बाद अगस्त 2024 में खारिज की गई। ये मुल्जिम वर्ष 2023 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

शांति एवं अहिंसा विभाग ने सुबोध महाविद्यालय में कराया सेमिनार

फर्जी डिग्री देने-लेने वालों पर कसा शिकंजा

सिंह ने बताया कि एसआईटी की जांच में ज्ञात हुआ कि पेपर लीक करने एवं डमी अभ्यर्थी की सहायता से चयन कराने वाले गैंग द्वारा बिना योग्यता वाले अभ्यर्थियों का अनुचित साधनों से चयन करवा दिया जाता था। परीक्षा का फार्म भरते समय उनके द्वारा यह घोषणा की जाती थी कि वे अमुक विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं किन्तु वे वास्तव में विद्यार्थी नहीं हो कर चयनित होने पर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लाकर एवं अनुचित तरीकों से बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। एसआईटी द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ गहनता से छानबीन बाद मुकदमा दर्ज किया गया है एवं जांच प्रगति पर है। ऐसे प्राइवेट विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, दलालों एवं कई

लाभार्थियों को गिरफ्तार किया गया है और वे अभी भी जेल में बन्द हैं। साथ ही एसओजी ने खेलों में फर्जी प्रमाण पत्र का गोरखबंधा उजागर कर इसमें संलग्न आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है।

हैल्पलाइन पर आमजन से मिल रही सटीक सूचनाएं

एडीजी एसओजी एवं एटीएस सिंह ने बताया कि एसआईटी की टीम ने गत एक साल में जिस प्रकार रात दिन एक करते हुए पेपर लीक के मामलों में लगातार तत्परता से ठोस कार्रवाई की है, उससे युवाओं के साथ-साथ आमजन में भी सिस्टम के प्रति भरोसा कायम हुआ है। एसआईटी द्वारा जारी हैल्पलाइन पर आमजन सजग प्रहरी के रूप में लगातार परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग कर चयनित लाभार्थियों के बारे में सटीक सूचना बढ-चढकर साझा कर रहे हैं। एक तरह से एसआईटी हैल्पलाइन ने जनता को पुलिस की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है।

शांति एवं अहिंसा विभाग ने सुबोध महाविद्यालय में कराया सेमिनार

जयपुर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के क्रम में शांति एवं अहिंसा विभाग, राजस्थान सरकार एवं एस.एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। सेमिनार में बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने युवा दिवस के अवसर पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया।

इस सेमिनार के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत रहे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है।





## एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ



**प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी.**  
(PPIUCD)

**लाखों महिलाओं ने अपनाई**  
आप भी अपनाएं, अनचाहे गर्भ की चिंता से मुक्ति पाएं

- ▶ प्रसव के बाद 48 घंटों में प्रशिक्षित चिकित्सक/कर्मियों से PPIUCD लगवाएं
- ▶ पुनः गर्भधारण चाहने पर आसानी से निकलवाएं
- ▶ बच्चों में अंतर रखने का सरल व सुरक्षित गर्भनिरोधक साधन

हर चौथे माह में अंतरा इन्जेक्शन लगवाएं  
अनचाहे गर्भ ठहरने की चिंता से मुक्ति पाएं

बच्चों में अंतर रखने का आसान व सुरक्षित...  
**अंतरा**  
—एम.पी.ए. इंजेक्शन—

तीन महीने के अंतराल पर स्वास्थ्यकर्मी से एक इंजेक्शन लगवाएं  
जब गर्भधारण चाहें, अंतरा लगवाना बंद कर दें।

सभी राजकीय जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी व स्वास्थ्य केन्द्रों पर  
परिवार नियोजन साधनों की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।  
अधिक जानकारी के लिए एएनएम/आशा सहयोगिनी से सम्पर्क करें।

**साधन-परामर्श हमारा : चयन-फैसला आपका**



**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईसीसी) राजस्थान, जयपुर






**श्री नरेन्द्र मोदी**  
माननीय प्रधानमंत्री



**श्री भजनलाल शर्मा**  
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

## मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव

13 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी  
के नियुक्ति पत्र का वितरण

31 हजार करोड़ रुपए के 76 हजार से अधिक  
विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

# राज्य स्तरीय समारोह

मुख्य अतिथि  
**श्री भजनलाल शर्मा**  
माननीय मुख्यमंत्री

विशिष्ट अतिथि  
**सुश्री दिया कुमारी**  
माननीया उप मुख्यमंत्री

**श्री जोगाराम पटेल**  
माननीय संसदीय कार्यमंत्री

12 जनवरी, 2025

प्रातः 11:00 बजे

बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर

निर्भाई जिम्मेदारी - हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान





## #DATA PROTECTION

### India's New Digital Rules



Social media apps and other platforms tend to keep your data for years but the new personal data rules will look to change that.



Data fiduciaries such as e-commerce, online gaming and social media platforms will have to erase personal data of a user three years after it is no longer required, according to the draft rules of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act.

The draft rules apply to e-commerce entities having not less than 2 crore registered users in India, online gaming intermediaries having not less than 50 lakh registered users in India and social media intermediaries having not less than 2 crore registered users in the country. These provisions pertain to Section 8 of the draft rules.

These data fiduciaries have to notify users at least 48 hours before erasing their data, allowing them to request for retaining the data if they wish to, like their profiles, email addresses and phone numbers, to access money, goods or services.

"At least forty-eight hours before completion of the time period for erasure of personal data under this rule, the Data Fiduciary shall inform the Data Principal that such personal data shall be erased upon completion of such period, unless she logs into her user account or otherwise initiates contact with the Data Fiduciary for the performance of the specified purpose or exercises her rights in relation to the processing of such personal data," according to draft rules. A data fiduciary will protect personal data in its possession or under its control, including in respect of any processing undertaken by it or on its behalf by a data processor by taking reason-



Map of India in 1765.



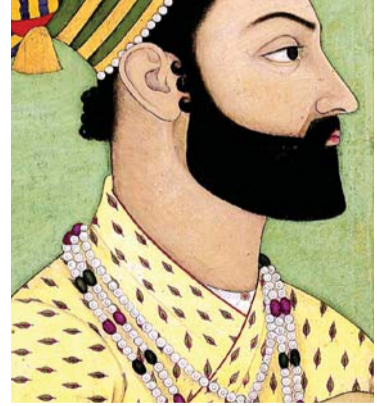
For the valour displayed by the Marathas in the third battle of Panipat, he was extolled by Ahmad Shah Abdali in his letter to his ally, Madho Singh, the king of Jaipur. He speaks of it.

The Marathas fought with the greatest valour, which was beyond the capacity of other races. These dauntless blood-shedders did not fall short in fighting and doing glorious deeds. Suddenly, the breeze of victory began to blow, and the wretched Deccanis suffered defeat.

The battle was referred to in Rudyard Kipling's poem 'With Scindia to Delhi'.

"Our hands and scarfs were saffron-dyed for signal of despair. When we went forth to Panipat to battle with the Mlech,

Ere we came back from Panipat and left a kingdom there." British (Scotts) Colonial Officer and Historian in India, Son of John Grant (d. 1799) and Margaret Duff educated at Marischal College in Aberdeen. Joined the E.I.C.'s military service in Bombay in 1805. He was at the



Ahmad Shah Durrani.

storming of Maliah, 1808, became Adjutant and Interpreter of his regiment, was Assistant to Mountstuart Elphinstone in Poona. "As captain, he served against the Peshwa, Bajji Rao, when the latter was dethroned in 1818, and was then made Resident of Satara, administering the state in the Raja's name till 1822, and making treaties with Satara jagirdars. After five years, he retired to Scotland" in c. 1823 and wrote there his book. He took the additional names, Duff and Cunningham, on succeeding to landed estates. He knew Marathi, Urdu and Persian. Married, two daughters and one son, Mountstuart Elphinstone Grant-Duff (1829-1906) was M.P. and Governor of Madras. In an interview in his book, he has confirmed the massive numbers of soldiers and civilians that perished in this battle of battles. It is, however, also remembered as a scene of valour on both sides. Atal Khan, the adopted son of the

The Marathas, under the command of Sadashivrao Bhau, responded by gathering an army of between 45,000 and 60,000, which was accompanied by roughly 200,000 non-combatants, a number of whom were pilgrims desirous of making pilgrimages to Hindu holy sites in northern India.

Wazir Shah Wali Khan, was said to have been killed during this time, when Yeshwantrao Pawar climbed atop his elephant and struck him down. Santaji Wagh's corpse was found with over 40 mortal wounds.

The Third Battle of Panipat took place on 14 January, 1761, between the Maratha Confederacy and the invading army of the Durrani Empire. The battle took place in and around the city of Panipat, approximately 97 kilometres (60 mi) north of Delhi. The Afghans were supported by three key allies in India, Najib ad-Dawlah, who persuaded the support of the Rohilla chiefs, elements of the declining Mughal Empire, and most prized, the Oudh State under Shuja-ud-Daula. The Maratha army was led by Sadashivrao Bhau, who was third-highest authority of the Maratha Confederacy after the Chhatrapati and the Peshwa. The bulk of the Maratha army was stationed in the Deccan Plateau with the Peshwa.

# "Ere we came back from Panipat And left a kingdom there"

PART: I

The battle lasted for several days and involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably.



Bajji Rao's army under the command of cousin, Sadashivrao Bhau.



Rudyard Kipling.

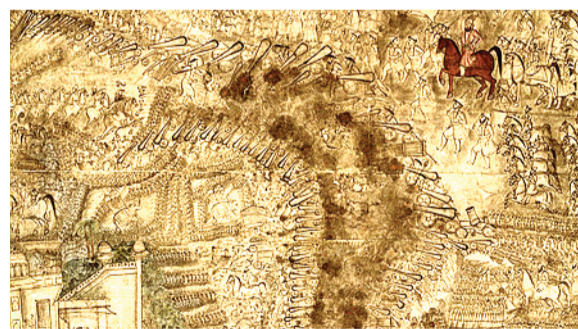
## #THE BATTLE OF ALL BATTLES



Grant Duff bungalow in Satara.

Involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably. According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

Militarily, the battle pitted the artillery, musketry, and cavalry of the Marathas against the heavy cavalry, musketry (jezzai) and mounted artillery (zamburak) of the Afghans and the Rohillas led by Abdali and Najib ad-Dawlah. The battle is considered to have been one of the largest and most eventful, fought in the 18th century, and it had, perhaps, the largest number of fatalities in a single day reported in a classic formation battle between two armies. The battle



According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

Involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably. According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

### Extent of the Maratha Confederacy, 1760

The 27-year Mughal-Maratha war (1680-1707) led to rapid territorial loss of the Maratha Empire to the

Mughal Emperor Aurangzeb. However, after his death in 1707, this process reversed following the Mughal succession war between the sons of Aurangzeb. By 1712, Marathas quickly started retaking their lost lands. Under Peshwa Bajji Rao, Gujarat, Malwa and Rajputana came under Maratha control. Finally, in 1737, Bajji Rao defeated the Mughals on the outskirts of Delhi and brought much of the former Mughal territories in the south of Agra under Maratha control. Bajji Rao's son, Balaji Bajji Rao, further increased the territory under Maratha control by invading Punjab in 1758. The changing circumstances of the Maratha forces and the declining position of the Mughal kingdom are clear from this document.

Raghnath Rao's letter to the Peshwa, 4 May, 1758. Lahore, Multan and other subahs on eastern side of Attock are under

Involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably. According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

Involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably. According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

Involved over 125,000 troops, protracted skirmishes occurred, with losses and gains on both sides. The Afghan army ultimately emerged victorious from the battle after successfully destroying several Maratha flanks. The extent of the losses on both sides is heavily disputed by historians, but it is believed that between 60,000 and 70,000 troops were killed in the fighting, while the numbers of injured and prisoners taken vary considerably. According to the single-best eyewitness chronicle, the *bakhar* by Shuja-ud-Daula's Diwan Kashi Raja, about 40,000 Maratha prisoners were collectively slaughtered on the day after the battle. British historian Grant Duff includes an interview of a survivor of these massacres in his *History of the Marathas*.

Muslims of Northern India, and Shuja-ud-Daula, forming a broad coalition against the Marathas.

To counter this, Raghnath Rao was supposed to go north to handle the situation. Raghnath Rao asked for large number of soldiers, which was denied by Sadashivrao Bhau, his cousin and Diwan of Peshwa. Therefore, he declined to go. Sadashivrao Bhau was instead made commander-in-chief of the Maratha Army, under whom the Battle of Panipat was fought.

The Marathas, under the command of Sadashivrao Bhau, responded by gathering an army of between 45,000 and 60,000, which was accompanied by roughly 200,000 non-combatants, a number of whom were pilgrims, desirous of making pilgrimages to Hindu holy sites in northern India. The Marathas started their northward journey from Partur on 14 March, 1760. Both sides tried to get the Nawab of Awadh, Shuja-ud-Daulah, into their camp. By late July, Shuja-ud-Daulah made the decision to join the Afghan-Rohilla coalition, preferring to join what was perceived as the 'army of Islam'. This was strategically a major loss for the Marathas, since Shuja provided much-needed finances for the long Afghan stay in North India. It is doubtful whether the Afghan-Rohilla coalition would have the means to continue their conflict with the Marathas without Shuja's support.

To be continued...

rajeshsharma1049@gmail.com



Sadashivrao Bhau.

## #SPACE COMMERCIALISATION

# Humans will soon be able to Mine on the Moon. But should we?

Now is the time to create rules and regulations that will protect humanity's shared future in space and ensure that the Moon remains a symbol and inspiration for generations to come.

By the end of this decade, nations and private companies may well be mining the surface of the Moon. But as space becomes accessible to more nations and corporations, we need to stop and ask ourselves what commercial activities we want to allow, including on the Moon. Now is the time to create rules and regulations that will protect humanity's shared future in space and ensure that the Moon remains a symbol and inspiration for generations to come.



### 1. Why Mine the Moon?

NASA's multibillion dollar Artemis program isn't just about sending astronauts back to the Moon. It's about paving the way for mining operations. China is also on a similar trajectory. All of this has set in motion a new lunar race, with private companies competing to figure out how to extract the Moon's resources, potentially selling it back to governments in a cosmic supply chain.

### 2. Could Mining change how we see the Moon from Earth?

When material is extracted from the Moon, dust gets kicked up. Without an atmosphere to slow it down, this lunar dust can travel vast distances. That surface material is 'space weathered' and duller than the more reflective material beneath. Disturbing the lunar dust means that some patches of the Moon

time a single litre of water reaches the Moon, its cost beats that of gold. But by converting water ice on the Moon into hydrogen and oxygen, we can refuel spacecraft on-site. This could make deeper space journeys, especially to Mars, far more feasible. The Moon's wealth of rare Earth metals, essential for technologies like smartphones, also means that lunar mining could ease the strain on Earth's dwindling reserves. Private companies might beat space agencies to the punch, a start-up could be mining the Moon before NASA lands its next astronaut.

may appear brighter, where the dust has been kicked up, while other patches may appear more dull, if dust resettles on top. Even small-scale operations might disturb enough dust to create visible changes over time. Managing lunar dust will be a crucial factor in ensuring sustainable and minimally disruptive mining practices.

### 3. Who Owns the Moon?

The Outer Space Treaty (1967) makes it clear that no nation can claim to 'own' the Moon (or any celestial body). However, it is less clear whether a company extracting resources from the Moon violates this non-appropriation clause. Two later agreements take up this issue.

- The 1979 *Moon Treaty* claims the Moon and its natural resources as 'common heritage of mankind'. This is often interpreted as an explicit ban on commercial lunar mining.
- The 2020 *Artemis Accords*, how-

ever, allow for mining while reaffirming the Outer Space Treaty's rejection of any claims of ownership over the Moon itself. The Outer Space Treaty also notes that the exploration of space should benefit everyone on Earth, and not just the wealthier nations and corporations able to get there. When it comes to resource extraction, some argue that this means all nations should share in the bounty of any future lunar mining endeavour.

### 4. What would Miners' lives be like on the Moon?



Imagine you've worked 12 hours straight in hot and dirty conditions! You are dehydrated, hungry and overwhelmed. Some of your co-workers have collapsed or been injured due to exhaustion. You all wish you could just get another job with good safety standards, fair pay and reasonable hours. But you can't. You're stuck in space. This dystopian vision highlights the potential dangers of rushing into lunar mining without addressing the risks to workers. Working in low gravity conditions brings health hazards. Lunar miners are more likely to suffer,

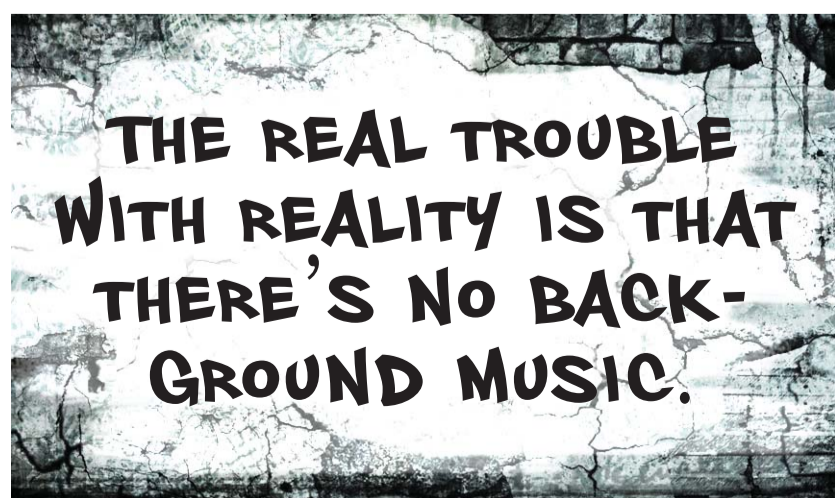
- bone and muscle loss
- osteoporosis
- renal and cardiovascular damage, and
- impaired immunity.

Exposure to cosmic radiation not only carries an increased risk of various cancers but can also affect fertility. Lunar miners will also face prolonged isolation and intense psychological stress. We'll need good laws and guidelines to protect the health and wellbeing of the space workforce.

Regulatory bodies to enforce worker rights and safety standards will be far away on Earth. Miners may be left with little recourse if asked to work unreasonable hours in unsafe conditions. The Moon holds incredible promise as a stepping stone for human exploration and a potential source of resources to sustain life on Earth and beyond. But history has shown us the consequences of unchecked exploitation. Before we mine the Moon, we must establish robust regulations that prioritise fairness, safety and human rights.



## THE WALL



## BABY BLUES



## ZITS













# मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर रिफाइनरी कार्मिकों में उत्साह दिखा

## श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई

बालोतरा, 10 जनवरी (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बालोतरा जिले में पंचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया एवं समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार एवं रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बस में बैठ कर रिफाइनरी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में ड्यूटी फीड क्रेकर यूनिट का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस यूनिट के निर्माण में बुजुर्ग खलीफा से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंचपदरा में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ बातचीत भी की।

कार्यों में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिफाइनरी और आस-पास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को एक विशेषाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो कि 15 दिन में रिफाइनरी परियोजना के प्रगतिगत कार्यों की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट बनाए।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के मॉडल का अवलोकन भी किया और रिफाइनरी परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्वा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल, प्रियंका चौधरी, अरुण चौधरी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताम शर्मा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत, रीको प्रबन्ध निदेशक इन्द्रजीत सिंह, एच.आर.आर.एल. के निदेशक एस. भारतन, सीईओ कमलाकर आर विखर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

# ‘मस्जिद के समीप के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखें’

■ सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाहीजामा मस्जिद के कुएं पर नगर पालिका के नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है।

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर, विवादित संभल मस्जिद के पास के कुएं का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय नगर पालिका की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस को 21 फरवरी, 2025 तक लागू नहीं करने और दो सप्ताह में स्थिति का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने संभल नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे पोस्टरों के माध्यम से जारी किए गए अपने सार्वजनिक नोटिस को लागू न करें, जिसमें शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया गया है तथा वह श्रद्धालुओं की पूजा व स्नान के लिए बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्री अदालत के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि उस जगह के आसपास की स्थिति शांतिपूर्ण थी, लेकिन आवेदक ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्नान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहा गया है।

जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मातृ भाषा में शिक्षा मिलने के कारण सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालों के अनुभव और समृद्ध संस्कृति का ह्रास होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।

# दिल्ली के बाकी प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा की बैठक

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केन्द्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की शुक्रवार देर शाम यहां पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई गयी, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिये जाने की उम्मीद है।

■ मोदी, अमित शाह, राजनाथ व नन्दा भी बैठक में शामिल हुए।

राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में दिल्ली विधानसभा की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। भाजपा द्वारा अब तक घोषित 29 प्रत्याशियों में बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का भी नाम है। पार्टी ने वर्मा को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उतारा है।

## ‘ई-सिगरेट की बिक्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसे हैरानी हुई कि राजस्थान सरकार की क्राइम ब्रांच ने इन सबालों के जवाब देने के लिये कोई भी रिकॉर्ड बरकरार नहीं रखा है, इससे साबित होता है कि राज्य सरकार इससे बेपरवाह है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में कई दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार को बार-बार कहा गया कि ई-सिगरेट रोकने के लिये कार्यवाही करें, लेकिन इसे रोकने के लिये केवल कागजी कार्यवाही की गई है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर के 2022 में दायर शपथ पत्र से ये ही जाहिर होता है कि ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये विभाग कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस विभाग की अपनी सीमाएं हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि शपथ पत्र दायर किये काफी समय हो गया है, उन्हें नया शपथ पत्र पेश करना होगा। अदालत ने कहा कि अगली तारीख पर जो अफसर ई-सिगरेट की बिक्री को मॉनिटर करने के लिये नियुक्त किये जायें, वे वी.सी. के जरिये अदालत में उपस्थित रहें। इस मामले में अगली तारीख 1 फरवरी 2025 तय की गई है।

## अश्विन अब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जाने गंवाई। पुराने लोग याद करते हैं कि तब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, हिंदी सम्बंधी फैसले ने राज्य में कांग्रेस को खलनायक बना दिया और उसके बाद द्रविड़ पार्टियां सत्तारुढ़ हुईं और तब से लेकर आज तक कांग्रेस अपने दम पर राज्य में पुनः सत्ता में नहीं आ पाई है।

कांग्रेस को राज्य में किसी न किसी द्रविड़ पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ता है, कभी द्रमुक से, तो कभी अनाद्रमुक से। फिलहाल दो दशक से कांग्रेस का द्रमुक से गठबंधन है।

अश्विन की टिप्पणी से तमिलनाडु में उनके प्रशंसक अवश्य बढ़ गए होंगे।

## कड़ाके की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विलंबित हैं और 26 ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भारतीय समयानुसार तड़के साढ़े चार बजे से पालम में दृश्यता शून्य है। मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के अनेक इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया है।

इस बीच राज्य के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 11 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।

## ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुक्त होकर व्हाइट हाउस जा सकेंगे। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉन स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में दोषी करार दिया गया था। ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान या पूर्व) हैं, जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रम्प की ओर से कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ, मैनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में सजा सुनाने का रास्ता खुल गया था।

ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें सजा सुनाया जाना एक ऐसा आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करता है, जिसका गवाह अमेरिका पहले नहीं है। कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की विशाल शक्तियां और देश के कानूनों और संविधान के अंतिम संरक्षक बनने वाले हैं।